पैकेटबंद फूड पर सरकार की सख्ती से कंपनियां नाराज

विशेषज्ञों ने कहा- पैकेट के सामने स्पष्ट चेतावनी से उपभोक्ताओं को स्वस्थ विकल्प चुनने में मिलेगी मदद

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 25 अगस्त भारत में पैकेटबंद खाद्य पदार्थों और मीठे पेय पर सामने स्पष्ट पोषण चेतावनी लेबल लगाने की कोशिश को लेकर सरकार, खाद्य नियामक और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीच खींचतान सामने आई है.

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने पैकेट के सामने रंगीन चेतावनी लेबल लगाने के प्रस्ताव पर नरम रुख अपनाते हुए चीनी, वसा और नमक की मात्रा बताने वाली ब्लैक-एंड-व्हाइट तालिका का विकल्प सुझाया है. वहीं, सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ और कार्यकर्ता अधिक स्पष्ट और आसानी से दिखाई देने वाले चेतावनी लेबल की मांग कर रहे हैं.

उनका तर्क है कि उपभोक्ताओं को उत्पाद में मौजूद अधिक चीनी, नमक और वसा की जानकारी पैकेट के सामने ही सरल तरीके से मिलनी चाहिए.मामला अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में भी है.

रिपोर्ट के अनुसार, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की याचिका के बाद अदालत ने चेतावनी लेबल के मुद्दे पर नियामकों से विचार करने को कहा है. विशेषज्ञों का कहना है कि पैकेट के सामने लाल-हरा या अन्य रंगों वाले स्पष्ट संकेत उपभोक्ताओं को बेहतर विकल्प चुनने में मदद कर सकते हैं. दुनिया के करीब 20 देशों में इस तरह की फ्रंट-ऑफ-पैक लेबलिंग व्यवस्था लागू है.विवाद का एक अहम पहलू बहुराष्ट्रीय खाद्य कंपनियों की अलग-अलग बाजारों में अलग रणनीति को लेकर है.

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कोका-कोला और नेस्ले जैसी कंपनियां यूरोप और ब्रिटेन में ट्रैफिक-लाइट शैली के पोषण लेबल या चेतावनियों का इस्तेमाल करती हैं, जबकि भारत में ऐसे अनिवार्य लेबल का विरोध कर रही हैं.

> कंपनियों का तर्क है कि केवल प्रतीक या चेतावनी देखकर उपभोक्ता अपनी खान-पान की आदतें नहीं बदलेंगे और प्रस्तावित व्यवस्था भ्रमित करने वाली हो सकती है. भारत में मोटापा और खान-पान से जुड़ी बीमारियों की बढ़ती चुनौती को देखते हुए उपभोक्ताओं को उत्पाद की पोषण संबंधी जानकारी आसानी से समझ आने वाले तरीके से उपलब्ध कराना जरूरी है. ऐसे में चेतावनी लेबल को लेकर जारी विवाद केवल पैकेजिंग का मुद्दा नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और उपभोक्ता के सूचना के अधिकार से भी जुड़ा हुआ है.

खर्च की ताकत में चीन से आगे भारत

अब चीन से भी आगे निकलेगा भारत

नवभारत न्यूज

नई दिल्ली, 25 अगस्तभारत दुनिया में बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है. इसके साथ ही देश में लोगों के खर्च करने की ताकत भी बढ़ रही है. एक रिपोर्ट के मुताबिक अमीर उपभोक्ताओं की संख्या के मामले में भारत 2036 तक चीन से आगे निकल जाएगा.

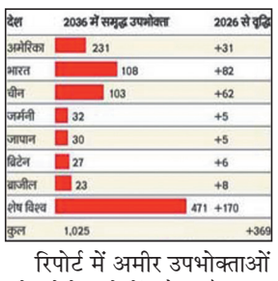

10 साल बाद भारत में रोजाना 90 डॉलर खर्च करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 10.8 करोड़ होगी, जबकि चीन में ऐसे 10.3 करोड़ उपभोक्ता होंगे. तब केवल अमेरिका ही हमसे आगे रह जाएगा. नीलसनआईक्यू और वर्ल्ड डेटा लैब की एक हालिया संयुक्त रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है.

रिपोर्ट में अमीर उपभोक्ताओं को ऐसे लोगों के तौर पर परिभाषित किया गया है जो रोजाना 90 डॉलर से ज्यादा खर्च करते हैं. अनुमान है कि अभी भारत में लगभग 2.6 करोड़ अमीर उपभोक्ता हैं और 10 साल में इसमें 8.2 करोड़ और जुड़ेंगे.

इस दौरान चीन में 6.2 करोड़ अमीर उपभोक्ताओं के जुड़ने का अनुमान है. अलग से यह भी अनुमान लगाया गया है कि 2026 में भारत में 64.9 करोड़ कोर कंज्यूमर्स होंगे.

खर्च करने की क्षमता लगातार मजबूत हो रही

भारत में बढ़ती आय, शहरीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था के विस्तार से उपभोक्ताओं की खर्च करने की क्षमता लगातार मजबूत हो रही है. आने वाले वर्षों में इसका सबसे ज्यादा फायदा रिटेल, ई-कॉमर्स, ट्रैवल, ऑटोमोबाइल, प्रीमियम उत्पादों और वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों को मिलने की उम्मीद है. विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे-जैसे मध्यम वर्ग की आमदनी बढ़ेगी, वैसे-वैसे भारतीय उपभोक्ता जरूरतों के साथ-साथ अनुभव और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पादों पर भी ज्यादा खर्च करेंगे.

चीन पर अमेरिका का नया टैरिफ वार

7.5 ′ शुल्क से भारत के लिए अवसर या नई चुनौती

यह बदलाव भारतीय उद्योग की लागत पर डाल सकता है असर

नवभारत न्यूज

नयी दिल्ली, 25 अगस्त अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार तनाव एक बार फिर बढ़ने के संकेत हैंअमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन चीन से आयात होने वाले सामान पर 7.5 प्रतिशत का अतिरिक्त टैरिफ लगाने की तैयारी कर रहा है.

हालांकि, इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है और दर में बदलाव की संभावना बनी हुई है. अमेरिका का आरोप है कि चीन अपनी जरूरत से ज्यादा उत्पादन कर रहा है और कमजोर घरेलू मांग के कारण कम कीमत पर सामान दूसरे देशों के बाजारों में भेज रहा है. इससे अमेरिकी कंपनियों और कारोबार पर दबाव बढ़ रहा है. प्रस्तावित शुल्क पहले से लागू टैरिफ के ऊपर लगाया जा सकता है, जिससे अमेरिका में चीनी सामान की कीमत बढ़ने की संभावना है. अमेरिका ने चीन की औद्योगिक क्षमता व्यापार नीतियों की जांच के लिए ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत कार्रवाई शुरू की है. चीन में इलेक्ट्रिक वाहन, सौर पैनल, स्टील, सीमेंट और अन्य उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है. घरेलू मांग कमजोर रहने के कारण चीन का निर्यात बढ़ा है और पिछले वर्ष उसका व्यापार अधिशेष करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया.

इस कदम का असर भारत समेत दुनिया की अन्य अर्थव्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है. यदि अमेरिका में चीनी उत्पाद महंगे होते हैं, तो भारतीय कंपनियों के लिए कुछ क्षेत्रों में अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने का अवसर बन सकता है. खासकर ऐसे उत्पादों में भारत को फायदा मिल सकता है, जहां वह चीन का विकल्प बन सकता है.

अमृत वृष्टि में 3 करोड़ तक निवेश

नयी दिल्ली, 25 अगस्त सुरक्षित निवेश के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट को पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक की 444 दिन वाली 'अमृत वृष्टि' एफडी एक विकल्प है. इस योजना में ग्राहक अपनी उम्र के हिसाब से अलग-अलग ब्याज दर का लाभ उठा सकते हैं. आम ग्राहकों के लिए ब्याज दर 6.45% सालाना है, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 6.95% और 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अति वरिष्ठ नागरिकों को 7.05% सालाना ब्याज मिलता है. हालांकि, एफडी कराने से पहले बैंक की मौजूदा ब्याज दरों और नियमों की जांच करना जरूरी है अमृत वृष्टि एफडी की अवधि 444 दिन तय है. 59 वर्ष तक की उम्र वाले सामान्य ग्राहकों को इस एफडी पर 6.45% सालाना ब्याज दिया जाता है.

भारत-जापान निवेश साझेदारी को मिलेगी रफ्तार

10 ट्रिलियन येन के जापानी निजी निवेश का लक्ष्य

भारत में 7.7% आर्थिक वृद्धि का गोयल ने किया उल्लेख

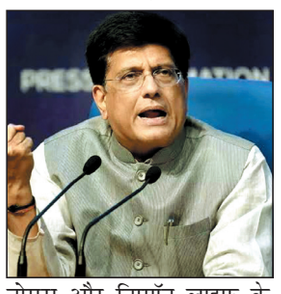

टोक्यो, 25 अगस्त भारत और जापान के बीच निवेश साझेदारी को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को टोक्यो में जापान की प्रमुख वित्तीय और निवेश संस्थाओं के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की.

बैठक में भारत में दीर्घकालिक जापानी पूंजी का प्रवाह बढ़ाने, निवेश के नए अवसर तलाशने और दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को नई गति देने पर चर्चा हुई. रूस्वत, डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान मिजुहो, मॉर्गन स्टेनली, नोमुरा और निप्पॉन लाइफ के वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने बैठक में हिस्सा लिया. गोयल ने जापानी निवेशकों को भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में मौजूद अवसरों से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत आर्थिक वृद्धि दर्ज कर रहा है और 2047 तक 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है.

जापानी कंपनियों का बढ़ता भरोसा

बैठक में जापानी वित्तीय संस्थाओं ने भी भारत में अपनी बढ़ती मौजूदगी और देश की दीर्घकालिक विकास संभावनाओं पर भरोसा जताया. रूस्वत ने भारत में श्रीराम फाइनेंस में करीब 4 अरब डॉलर के निवेश और नवीकरणीय ऊर्जा तथा हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में रुचि की जानकारी दी. डीबीजे ने भारत के लिए अपनी समर्पित निवेश रणनीति और रियल एस्टेट व वेंचर कैपिटल जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक निवेश की संभावनाओं का उल्लेख किया. मिजुहो ने भारत में जापानी कंपनियों की बेहतर लाभप्रदता और पुणे स्थित अपने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के विस्तार की जानकारी दी.

गिरावट से उबरे शेयर बाजार

नवभारत न्यूज

मुंबई, 25 अगस्त लगातार गिरावट के बाद मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार में तेजी लौटी. खरीदारी के जोर से सेंसेक्स 286.98 अंक यानी 0.37 प्रतिशत बढ़कर 77,656.09 अंक पर बंद हुआ. वहीं निफ्टी-50 सूचकांक 115.50 अंक यानी 0.48 प्रतिशत की बढ़त के साथ 24,334.55 अंक पर पहुंच गया. बाजार में चुनिंदा प्रमुख शेयरों में खरीदारी से निवेशकों का रुझान सकारात्मक रहा और प्रमुख सूचकांकों ने शुरुआती दबाव से उबरते हुए बढ़त हासिल की.

मिर्गी रोग की सही पहचान और समय पर इलाज जरूरी : डॉ. डोंगरे

नवभारत, जबलपुर। मस्तिष्क में अचानक होने वाली असामान्य विद्युत गतिविधि के कारण होने वाली मिर्गी बीमारी का सही इलाज और नियंत्रण पूरी तरह संभव है। ये बातें मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल नागपुर के न्यूरोलॉजी सीनियर कंसल्टेंट डॉ. निखिल डोंगरे ने कहीं। डॉ. डोंगरे ने आगे बताया कि सही इलाज और सामाजिक सहयोग मिलने पर मिर्गी पीड़ित लोग सामान्य और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह बीमारी छूने से नहीं फैलती है और दौरे रोकने वाली दवाएं इसके इलाज का मुख्य हिस्सा हैं, जिससे मरीजों के दौरे अच्छी तरह नियंत्रित हो जाते हैं। चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को दौरा पड़ता है तो उसे सुरक्षित स्थान पर एक करवट लिटाना चाहिए और दौरे के दौरान उसे जबरन पकड़ने या मुंह में कुछ भी डालने से बचना चाहिए। यदि दौरा पांच मिनट से अधिक समय तक रहे या सांस लेने में परेशानी हो, तो तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए। बीमारी को नियंत्रित करने के लिए समय पर इसकी पहचान, नियमित डॉक्टर की सलाह और निर्धारित दवाओं को सही तरीके से लेना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, जिसका उद्देश्य समाज में इस बीमारी से जुड़ी गलतफहमियों को कम करना है।

अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित

कोलकाता। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से राजभाषा हिंदी के प्रभावी एवं प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगीत, दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुआ। उद्घाटन सत्र में रेलटेल पूर्वी क्षेत्र के प्रधान कार्यकारी निदेशक जाकिर हुसैन सिद्दीकी ने हिंदी के प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए संगठन में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। इस दौरान राजभाषा गतिविधियों पर प्रस्तुति के साथ हिंदी पत्रिका 'तविशी' के विशेषांक का विमोचन भी किया गया। सम्मेलन में रेलटेल के निदेशक/पीओएम मनोज टंडन ने स्वरचित कविता का पाठ किया, जबकि नराकास के सदस्य सचिव राजेश बी. नायर ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए रेलटेल की पहल की सराहना की। रेलटेल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक संजय कुमार ने गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों के कर्मचारियों को हिंदी सीखने और दैनिक कार्यालयीन कार्यों में इसका अधिकाधिक प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं के समान सम्मान पर जोर दिया। मुख्य अतिथि मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक प्रेम सागर गुप्ता ने कहा कि हिंदी को केवल औपचारिक आयोजनों तक सीमित रखने के बजाय दैनिक जीवन और व्यवहार का स्वाभाविक हिस्सा बनाया जाना चाहिए। सम्मेलन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और राजभाषा के बदलते स्वरूप पर भी मंथन हुआ।

साझा किए गए विचार

एआईएलजीओ टेक्नोलॉजीज, दुबई के सीईओ बालेन्दु शर्मा 'दाधीच' ने 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता और राजभाषा: अवसर, चुनौतियाँ एवं भविष्य' विषय पर व्याख्यान दिया।

स्टार हेल्थ ने जबलपुर में खोला नया जोनल कार्यालय

नवभारत, जबलपुर। स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने जबलपुर में अपने पहले जोनल कार्यालय का शुभारंभ करके राज्य में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया है। यह कार्यालय जेडीए योजना क्रमांक 5, एसबीआई चौक पर स्थित है। यह कार्यालय स्थानीय ग्राहकों की पहुंच को बेहतर बनाएगा और क्लेम समाधान की प्रक्रिया में तेजी लाएगा। कंपनी ने मध्य प्रदेश में अपनी स्थापना से अब तक लगभग 77 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया है, जहाँ उसके पास करीब 30,000 एडवाइजर और 350 नेटवर्क अस्पतालों का मजबूत नेटवर्क मौजूद है। इस अवसर पर स्टार हेल्थ के मध्य प्रदेश बिजनेस हेड नितिन मलिक ने कहा कि जबलपुर में पहले जोनल कार्यालय की शुरुआत स्थानीय स्तर पर सेवा को अधिक तेज और सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कंपनी ने मध्य प्रदेश में इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 85 करोड़ रुपये से अधिक के क्लेम का निपटारा किया है और ग्रॉस रिटन प्रीमियम में 11 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है।

समाचार विशेष

सज्जन कुमार पर हुड्डा के बयान से घिरी कांग्रेस

चंडीगढ़, 25 अगस्त. हरियाणा से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा की ओर से 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी व पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को अपना रोल माडल बताने के बाद पंजाब की राजनीति में यह मुद्दा गरमाया हुआ है.

हुड्डा के इस बयान के बाद पंजाब कांग्रेस विरोधी दलों के निशाने पर आ गए हैं. हालात यह हैं कि पंजाब कांग्रेस के नेताओं को बयान जारी कर कहना पड़ रहा है कि हुड्डा का बयान उनका निजी है, इससे कांग्रेस का कोई संबंध नहीं है. इसके बावजूद आम आदमी पार्टी (आप), भाजपा और शिरोमणि अकाली दल (शिअद) ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है.

पंजाब में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इस घटनाक्रम का राजनीतिक तौर पर नुकसान का अंदाजा लगाते हुए पंजाब के कांग्रेस नेताओं ने न सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा के बयान से पल्ला झाड़ लिया, बल्कि सज्जन कुमार का नाम तक लेने को पाप की संज्ञा तक दे डाली है. सज्जन कुमार की 20 अगस्त को सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई थी. दीपेंद्र हुड्डा के बयान को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग द्वारा उनकी निजी राय बताना, पूर्व सीएम चरनजीत सिंह चन्नी द्वारा सज्जन कुमार का नाम लिए जाने को पाप समान करार देना व अन्य कांग्रेस नेताओं द्वारा खुद को तटस्थ रखने का एक कारण यह भी है कि हुड्डा के बयान से सिख भाईचारे में 1984 के सिख विरोधी दंगों की याद ताजा कर दी है.

'मैंने कभी रोल मॉडल नहीं कहा : दीपेंद्र हुड्डा

अखिल भारतीय कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य एवं रोहतक के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सज्जन कुमार को लेकर अपने बयान पर रविवार को सफाई दी. उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़-मरोड़ पेश किया जा रहा है. उनके बयान में 'रोल माडल' जैसा अंग्रेजी का शब्द डालकर ऐसा अर्थ प्रचारित किया जा रहा है, जो उन्होंने कहा ही नहीं था और न ही उनकी ऐसी कोई मंशा थी. उन्होंने विशेष रूप से सिख समाज से जुड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर किसी भाई की भावनाओं को उनके बयान से ठेस पहुंची है तो वह खेद प्रकट करते हैं. 1984 के सिख विरोधी दंगों का जिक्र करते हुए कहा कि सिख समाज के न्याय की लड़ाई में भी वे उनके साथ हैं.

8वीं पास की थी पात्रता, 12वीं से ऊपर वाला नहीं चाहिए था

ओवर क्वालिफाइड चपरासी की गई नौकरी

नवभारत न्यूज नेटवर्क

दिल्ली, 25 अगस्त. भारत में सरकारी नौकरी में आम तौर पर ज्यादा शैक्षणिक योग्यता को बेहतर माना जाता है लेकिन क्या किसी पद के लिए तय अधिकतम शैक्षणिक योग्यता से ज्यादा पढ़ा-लिखा होना भी उम्मीदवार को अपात्र बना सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल पर महत्वपूर्ण कानूनी स्थिति स्पष्ट की है. दरअसल, मामला तमिलनाडु का है जहां एक संस्थान में एक अस्थायी ऑफिस अटेंडर की नियुक्ति निकाली गई. नियोक्ता ने रोजगार कार्यालय को भेजी मांग में साफ किया था कि उम्मीदवार ने कम से कम 8वीं कक्षा पास की हो लेकिन वह 12वीं/इंटरमीजिएट या उससे अधिक योग्यता प्राप्त न कर चुका हो. ऐसे मेंआवेदन करते वक्त स्नातक पास युवक ने नौकरी न मिलने की हताशा में अपनी शैक्षणिक योग्यता छिपाकर आवेदन किया और 8वीं पास योग्यता की जरूरत वाली नौकरी पा ली. बाद में जब नियोक्ता के स्तर पर यह बात मालूम चली तो उसने स्नातक पास युवक को ओवर क्वालिफाइड बताते हुए नौकरी से बर्खास्त कर दिया. फैसले से असंतुष्ट युवक ने न्याय की आशा में अदालत का रुख किया. मामला जब मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट ने इसे अन्याय माना और स्नातक पास युवक की नौकरी बहाल कर दी. फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नियोक्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की. सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतर बताया कि किसी उम्मीदवार का अधिक योग्य होना अपने आप में हर नौकरी के लिए पात्र नहीं बनाता.

पात्र प्रत्याशी होता है प्रभावित

कोर्ट ने कहा कि कम योग्यता वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित पद पर अधिक योग्य व्यक्ति नियुक्त हो जाता है तो उस पद के वास्तविक पात्र उम्मीदवारों का अवसर प्रभावित होता है. सार्वजनिक रोजगार पात्र उम्मीदवारों को ही मिलना चाहिए, यह फैसला खास तौर पर उन सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र की भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जिनमें अधिकतम शैक्षणिक योग्यता भी भर्ती की शर्त की हिस्सा होती है.

कुमारस्वामी का नए तरह का प्रचार!

नई दिल्ली, 25 अगस्त. दक्षिण के राज्य राजनीति में भी अक्सर नए प्रयोग करते हैं. केंद्रीय मंत्री और जेडीएस के नेता एचडी कुमारस्वामी का ऐसा ही एक प्रयोग देखने को मिला.

रविवार को दिल्ली के कई बड़े अंग्रेजी अखबारों का पहला पूरा पन्ना कर्नाटक सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप की खबरों और टिप्पणियों से भरा था. उसमें कुमारस्वामी की पार्टी का नाम या चुनाव चिन्ह नहीं था. उनकी फोटो भी नहीं थी. उनका सिर्फ एक बड़ा सा कमेंट छपा था, जिससे अंदाजा होता है कि यह विज्ञापन उन्होंने या उनकी पार्टी ने छपवाया है. इस विज्ञापन में अपनी ओर से कुछ नहीं कहा गया है.

कर्नाटक हाई कोर्ट के एक फैसले को विस्तार से छाप दिया गया है. असल में जुलाई के अंत में हाई कोर्ट ने एक फैसले में कहा कि हजारों करोड़ रुपए की बेंगलुरु मैसुरु इंफ्रास्ट्रक्टर कॉरिडोर यानी बीएमआईसी कर्नाटक के सबसे बड़े घोटालों में से एक है.

विशेष | मायावती के पोस्ट ने फिर जगाई उप्र की सियासी चर्चा

बसपा का ब्राह्मण फॉर्मूला और 2027 की तैयारी

लखनऊ, 25 अगस्त. यूपी की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर अपने पुराने 'सर्वसमाज' और सामाजिक इंजीनियरिंग के फॉर्मूले की ओर लौटती दिखाई दे रही है. मायावती ने एक पोस्ट कर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों, उम्मीदवारों के चयन और पार्टी के विधानसभा स्तर के सम्मेलनों में नामों की घोषणा का जिक्र किया है. खास तौर पर ब्राह्मण समाज को लेकर पार्टी की सक्रियता ने 2007 के विधानसभा चुनाव की यादें ताजा कर दी हैं.

सवाल यह है कि 2007 में ऐसा क्या हुआ था, जिसने बसपा को उत्तर प्रदेश में अपने दम पर बहुमत तक पहुंचा दिया था?

2027 के लिए मायावती का स्पष्ट संकेत

मायावती के हालिया पोस्ट में जिस तरह उम्मीदवारों के चयन, नामों की घोषणा और विधानसभा स्तर के सम्मेलनों की बात कही गई है, उससे यह संकेत मिलता है कि बसपा चुनाव से काफी पहले अपना संगठनात्मक और उम्मीदवार चयन का काम शुरू करना चाहती है. ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या बसपा 2007 की तरह दलित आधार के साथ ब्राह्मण और दूसरे सवर्ण वर्गों को जोड़कर व्यापक सामाजिक गठबंधन फिर खड़ा कर पाएगी? दूसरा सवाल उम्मीदवारों का होगा. 2007 में 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संदेश भी था. इस बार बसपा कितने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारती है, किन सीटों पर उतारती है और क्या उन उम्मीदवारों के साथ पार्टी का पारंपरिक दलित वोट ट्रांसफर होगा.

2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बसपा ने 403 सीटों पर चुनाव लड़ा और लगभग 30 प्रतिशत वोट शेयर के साथ 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया. यह पार्टी का अब तक का सबसे बड़ा विधानसभा प्रदर्शन रहा है. उस विधानसभा चुनाव में बसपा ने ऊंची जातियों को अपने साथ जोड़ने की रणनीति पर खास जोर दिया. बसपा ने कुल 86 ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट दिया था. इसके अलावा ठाकुर, वैश्य समेत अन्य सवर्ण समुदायों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया. उस वक्त बसपा की सूची में 139 उम्मीदवार ऊंची जातियों से थे, जिनमें 86 ब्राह्मण थे. यही वह दौर था जब मायावती ने सतीश चंद्र मिश्र को बसपा के प्रमुख ब्राह्मण चेहरे के तौर पर आगे किया और प्रदेशभर में ब्राह्मण-दलित 'भाईचारा' सम्मेलनों के जरिए सामाजिक समीकरण बनाने की कोशिश हुई.

2007 की सफलता सिर्फ उम्मीदवारों की जातीय संख्या से नहीं समझी जा सकती है. सीएसडीएस के चुनाव अध्ययन के अनुसार 2007 में ब्राह्मण मतदाताओं में बसपा का समर्थन सीमित था, जबकि दलित खासकर जाटव मतदाताओं में बसपा का समर्थन बेहद मजबूत था. अध्ययन में जाटव मतदाताओं के बीच बसपा का समर्थन लगभग 86 प्रतिशत दर्ज किया गया. वहीं गैर-जाटव दलित और कुछ गैर-यादव ओबीसी समूहों में भी बसपा को खूब समर्थन मिला.